साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 07-13 फरवरी 2022, वर्ष-7, अंक-45

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

2022-23 का अम बजट: मेरा गांव, मेरा देश की दिखी झलक

'सीता' ने किसान को 'साधा'

- आयकर में छूट नहीं, मिडिल क्लास मायूस, कॉरपोरेट को राहत
- वित्त मंत्री सीतारमण ने चौथी बार आम बजट पेश किया
- 91 मिनट भाषण दिया, ये अब तक का सबसे छोटा भाषण
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैबलेट पर बजट भाषण पढ़ा
- जल जीवन मिशन को बजट में मिला बूस्टर डोज
- 60 हजार करोड़ से 3.8 करोड़ घरों में पहुंचेगा पानी
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा
- सौर क्षमता के लिए 19,500 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन
- कटे और पॉलिश किए गए हीरे, रत्नों पर सीमा शुल्क घटाई
- कॉरपोरेट सरचार्ज 12त्न से घटाकर 7त्न किया जाएगा
- रिकॉर्ड 1,40,986 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह
- कॉरपोरेट सरचार्ज 12फीसदी से घटाकर 7 फीसदी किया
- वर्चुअल डिजिटल असेट से आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स

मोदी बोले-बजट का एक अहम पहलू-गरीब का कल्याण

समृद्ध, शक्तिशाली, विकसित को मिलेगी गतिः शिव

बजट में नहीं है किसानों को एमएसपी की गारंटीःनाथ

ये बजट 25 साल की बुनियाद रखेगा। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाएंगे। आरबीआई के डिजिटल रुपए के अलावा क्रिप्टो वर्ल्ड में मौजूद सभी क्राइन वर्चुअल असेट्स में गिने जाएंगे। इनके लेन-देन में अगर किसी को मुनाफा होता है तो हम उस पर 30 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा।

निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री

नई दिल्ली।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट लोकसभा में पेश किया। किसानों, युवाओं के साथ ही उद्यमियों के लिए बड़े ऐलान किए गए। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विदेश से आने वाली मशीने महंगी होंगी। वहीं मोबाइल, मोबाइल चार्जर, जूते, चमड़े के बनी वस्तुएं, कपड़े, खेती से जुड़ी चीजें और हीरे वाले जेवर सस्ते होंगे। अगले 3 सालों में 400 नई वंदेभारत ट्रेनें चलाए जाएंगे। एक स्टेशन-एक पार्सल सुविधा शुरू की जाएगी। नए वित्त वर्ष में सरकार ने 60 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। पीपीपी के तहत राष्ट्रीय रोपवे कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 100 गति शक्ति कार्गो बनाए जाएंगे। किसानों को डिजिटल सर्विस दी जाएगी। पांच बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना का भी एलान किया। देश में निजी निवेश बढ़ाया जाएगा। डिजिटल विश्व विद्यालय स्थापित किया जाएगा। आईटी और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। ऑर्गेनिक खेती पर जोर रहेगा। पर्वतमाला प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाएगा। ड्रोन शक्ति योजना पर काम किया जाएगा। नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा। युवाओं के कौशल का विकास होगा। 80 लाख मकान बनाए जाएंगे, शहर गांव दोनों में इसके लिए 48 हजार करोड़ का आवंटन किया गया है। टेली मेंटल कार्यक्रम तैयार है, 1 से 12 तक के छात्रो के लिए 200 टीवी चैनल खोले जाएं। दो लाख आंगनवाड़ियों को बेहतर किया जाएगा। सीमावर्ती गांव को कनेक्टिवीटी में जोड़ा जाएगा। पीएम आवास योजना के लिए 40 हजार करोड़ दिए जाएंगे।

बजट से किसानों को क्या मिला

नए वित्त वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीद की जाएगी। सरकार ने इस साल के लिए 2.7 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। सिंचाई-सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इस किस्म की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार सुविधाएं देंगी। रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। साथ ही तिलहन की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। फल, सब्जी, किसान को पैकेज मिलेगा। कृषि क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में तेजी लाई जाएगी। केमिकल फ्री नैचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, तेल-तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाएंगे, ड्रोन के जरिए कृषि पर जोर देंगे, एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने पर फोकस रहेगा।

5 बड़ी घोषणाएं

- एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की जाएगी
- ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
- सिंचाई को बढ़ाने पर जोर
- 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित
- तिलहन को बढ़ावा दिया

सात योजनाओं को ज्यादा बजट

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: इस बार 37800 करोड़ रुपए आवंटित किया है। पिछले वित्तीय सत्र यानी 2021-22 के मुकाबले इसमें 2853 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

जल जीवन मिशन: इस बार इस योजना के लिए 60 हजार करोड़ आवंटित किए। पिछली बार के मुकाबले 14,989 करोड़ अधिक है। 2021-22 में 45011 करोड़ दिए गए थे।

राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: सरकार ने 39553 करोड़ का बजट आवंटित किया है। 2021-22 में इसके लिए 30796 करोड़ आवंटित किए गए थे। इसमें 8757 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है।

पीएम ग्राम सड़क: बजट में केंद्र सरकार ने 19000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पिछली बार यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 में इसके लिए 14000 करोड़ दिए गए थे।

पीएम किसान: इस बार बजट में 68000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। पिछली बार 67500 करोड़ दिया गया था। अब एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार: देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाने के लिए इस योजना को बजट में 6400 करोड़ दिए गए हैं। पिछली बार 5000 करोड़ आवंटित हुए थे।

पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा: लोगों को सस्ता और अच्छा इलाज मुहैया कराना है। इसके लिए इस बार बजट में 10 हजार करोड़ आवंटित किए हैं। पिछली बार 7400 करोड़ दिए गए थे।

ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने

के साथ ही सामान्य लोगों के लिए, अनेक नए अवसर बनाएगा। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68 फीसदी घरेलू इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ, भारत के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। ये बजट नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है- गरीब का कल्याण।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

यह नए भारत के निर्माण का बजट है। अधोसंचरना विकास के लिए 35 प्रतिशत से

ज्यादा राशि बजट में बढ़ाई गई है। इससे अधोसंचरना के विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मध्य प्रदेश को बढ़ी सौगात मिली है। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत कैन और बेतवा को जोड़ने पर 44 हजार करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च की जाएगी। किसानों की आय दोगुना होगी।

शिवराज सिंह चौहान, सीएम

केन्द्र का बजट पूरी तरह से निराशाजनक साबित हुआ है। यह महज आंकड़ों की

बाजीगरी से भरा व फिर झूठे सपने दिखाने वाला साबित हुआ है। इस बजट में किसी भी वर्ग के लिए कुछ नहीं है। आमजन इनकम टैक्स स्लैब में छूट बढ़ाने की मांग बड़े लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन कोई राहत प्रदान नहीं की गई। एमएसपी की गारंटी पर इस बजट में कोई बात नहीं है। किसानों की आय दोगुनी करने के झूठे सपने दिखाए गए हैं।

कमलनाथ, पूर्व सीएम

यह बजट आगामी 25 वर्षों में भारत की वैभवता और सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को केंद्रित करता है, जिसमें हर वर्ग के कल्याण

को ध्यान में रखा गया है। यह बजट पं. दीनदयाल के अंत्योदय के विचार को साकार कर रहा है। यह बजट सबका साथ,सबका प्रयास,सबका विश्वास और सबका विकास के मंत्र को साकार करने वाला है। यह ऐतिहासिक बजट गरीब,किसान, नौजवान, मध्यमवर्गीय परिवार, व्यापारी, दलित, पिछड़ा, महिला समेत हर वर्ग के लिए कल्याणकारी साबित होगा।

वीडी शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष भाजपा

भाजपा सरकार का बजट सशक्त, समृद्ध, समावेशी एवं सर्वस्पर्शी है। बजट में बड़े रिफॉर्म आधुनिक भारत के निर्माण के लक्ष्य

केंद्रित हैं। वित्त मंत्री ने बजट में गांव, गरीब, किसान और मजदूरों पर पूरा स्नेह बरसाया है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड का यह अमृत बजट है। यह बजट आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप तथा सबका साथ, सबका विकास के मूलमंत्र पर आधारित होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के लक्ष्य को पूर्ण करता है।

भरतलाल पांडेय, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा

फिर गांव की ओर चली सरकार

धान-गेहूं की एमएसपी पर खरीद बढ़ाने की घोषणा भी प्राकृतिक खेती, किसान ड्रोन की बातें जोर-शोर से की एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक स्टेशन एक उत्पाद

भोपाल/नई दिल्ली। संवाददाता

साल 2022-23 के लिए कृषि और उससे जुड़े सेक्टर का बजट 151521 करोड़ रुपए है। साल 2021-22 का बजट अनुमान 148301 करोड़ रुपए थे। साल 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया गया है। साल 2021-22 में 163 लाख किसानों से 2018 मीट्रिन धान गेहूं खरीदने का लक्ष्य है, जिसके एवज में उनके खातों में 2.37 लाख करोड़ रुपए जाएंगे। संसद में बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हों। कृषि में नए एग्री स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिले। फूड प्रोसेसिंग के लिए नए पैकेज हो, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। आम बजट को वित्त मंत्री ने भारत के अगले 25 साल का ब्लू प्रिंट बताया। जिसमें किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं देने का जिक्र किया गया। किसान ड्रोन के जरिए खेतों में फसल का आंकलन और रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। मप्र से पश्चिम बंगाल तक गंगा के किनारे बसे राज्यों में गंगा के 5 किलोमीटर के कॉरिडोर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट के मुताबिक कृषि और ग्रामीण उद्यमों से संबंधित स्टार्ट-अप्स के वित्त पोषण के लिए कोष की शुरुआत की जाएगी। बुंदेलखंड में 44605 करोड़ रुपए की केन बेतवा लिंक योजना से 62 लाख लोगों के फायदे की बात की गई है। जिसमें 9.08 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तरह ही अब वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट अगले 25 सालों की बुनियाद होगा। उन्होंने कहा कि एक स्टेशन, एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा। रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा। स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए एक स्टेशन, एक उत्पाद योजना शुरू होगी। ग्रामीण इलाकों के छोटे किसानों की मदद करने के लिए भारतीय रेलवे एक योजना तैयार करेगा। यह किसानों और कृषि-उद्यमों के लिए अधिक कुशल रसद विकसित करने में मदद करेगा और स्टेशनों से गुजरने वाले व्यापक दर्शकों, यानी रेलवे यात्रियों के लिए अद्वितीय क्षेत्रीय उत्पाद पेश करेगा। एक स्टेशन, एक उत्पाद सरकार के एक जिला, एक उत्पाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा जिसने भारत के हर जिले के उत्पादों को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया जा रहा है। रेलवे छोटे किसानों और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए नए उत्पादों और कुशल रसद सेवाओं का विकास करेगा, इसके अलावा पार्सल की आवाजाही के लिए निर्बाध समाधान प्रदान करने के लिए डाक और रेलवे नेटवर्क के एकीकरण में अग्रणी होगा।

किसान सम्मान निधि न बढ़ने से निराश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुचर्चित और फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए साल 2022-23 में 68000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में पीएम किसान के लिए बजट अनुमान 65000 करोड़ रुपए था जो संसोधित अनुमान में 67500 करोड़ हो गया था। वहीं 2020-21 में इस मद में 60990 करोड़ रुपए शामिल थे। योजना के तहत लघु और मध्यम किसानों को साल 2000 रुपए की तीन किस्तों में 6000 रुपए सीधे उनके खातों में भेजे जाते हैं। खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए किसान और किसान नेता पीएम किसान निधि में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे उन्हें हताशा हाथ लगी है।

उर्वरक बजट में कटौती

पिछला पूरा साल खाद संकट से गुजरा है। साल 2022-23 में उर्वरक का अनुमानित बजट 105222 करोड़ रुपए है जो 2021-22 के अनुमान (79530 करोड़ रुपए) ज्यादा है। लेकिन संसोधित बजट अनुमान 140122 करोड़ रुपए से कम है। इसके अलावा यूरिया सब्सिडी की बात करें तो साल 2022-23 के लिए 63222 करोड़ का आवंटन हुआ जो 2021-22 के अनुमान (58768) और संसोधित (75930) से कम है।

प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का बजट बढ़ा

प्रधानमंत्री सिंचाई योजना माइक्रो इरीगेशन के यानि मोर क्रॉप पर ड्रॉप के तहत साल 2022-23 में 12954 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित है। साल 2021-22 के बजट अनुमान 11588 और संसोधित अनुमान 12706 करोड़ रुपए था। साल 2020-21 में ये बजट 7877 करोड़ रुपए का था। योजना के तहत ड्रिप इरीगेशन, रेन गन आदि योजनाओं के लिए सब्सिडी दी जाती है। माइक्रो इरीगेशन में केंद्र के अलावा राज्य सरकारों भी सब्सिडी में अपना हिस्सा देती हैं। इस तरह माइक्रो इरीगेशन पर सब्सिडी 50 फीसदी से लेकर 85 फीसदी तक पहुंचती है, लेकिन इसमें नियम-कायदे बाधा बनते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कटौती

किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, बरिश, ओला सूखा, आदि के जोखिम दौरान मदद के लिए संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में साल 2022-23 के दौरान बजट अनुमान 15500 करोड़ का है। हालांकि साल 2021-22 का बजट अनुमान 16000 करोड़ का था जो जो संसोधित अनुमान 2021-22 में 15989 रुपए का हो गया था। साल 2020-21 का वास्तविक बजट 14161 करोड़ का था। साल 2021 प्राकृतिक आपदाओं का साल रहा है। यूपी, बिहार,महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और मध्य प्रदेश तक भारी अतिवृष्टि, बाढ़ की चपेट में रहे तो गुजरात का एक हिस्सा सूखे की मार भी झेल चुका है। ऐसे में किसानों को उम्मीद थी की फसल बीमा योजना के मद में बजट में बढ़ोतरी होगी।

कृषिन्नति योजना को फिर बजट आवंटित

कृषिन्नोति योजना में 7183 करोड़ रुपए का आवंटन। साल 2020-21 और 2021-22 में इस योजना के मद में कोई बजट आवंटित नहीं था। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए शुरु की गई कृषिन्नोति योजना को साल 2018 में 33269.79 करोड़ का बजट आवंटित हुआ था। यह एक तरह की छतरी योजनाएं, जिसमें 11 योजनाएं शामिल हैं। योजना के मूल में कृषि में वैज्ञानिक तरीकों के अपनाने पर जोर था। माना जा रहा है किसान ड्रोन जैसी घोषणाएं इसी योजना के तहत मूर्त रूप लेंगी।

सोलर पंप और सोलर ग्रिड

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों अपने खेत और बंजर जमीन पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। योजना के मद में इस साल 1716 करोड़ आवंटित किए गए हैं। योजना के तहत 90 फीसदी तक सब्सिडी पर किसान अपने खेतों में 2, 3 और 5 मेगावॉट के सोलर पंप लगा सकते हैं। इस योजना को अरुण जेटली के कार्यकाल में 2018-19 में शुरु किया गया था। शुरुआत में योजना सिर्फ बिजली से प्रभावित इलाकों में थी लेकिन योजना का लक्ष्य देशभर के सभी बिजली और डीजल से संचालित पंपों को सोलर से जोड़ने की है। वित्त वर्ष 2022-23 में किसान सोलर (ग्रिड) योजना के तहत 3304 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। योजना के तहत लाभकारी किसान न सिर्फ अपने लिए बिजली उत्पादन कर सकते हैं बल्कि शेष बिजली को ग्रिड को बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ऐसे इलाकों के किसानों को लाभ पहुंचाना है जहां पर जमीन खेती योग्य नहीं है।

सीएम शिवराज सिंह बोले-अमृत काल में प्रदेश की तकदीर बदलने के लिए टीम मध्यप्रदेश प्रतिबद्ध

प्राकृतिक खेती को करो प्रोत्साहित और मोटे अनाज उत्पादन का बढ़ाओ रकबा

- बिना एक क्षण गवाएं, प्रदेश के विकास और उन्नति के लिए निरंतर कार्य करें
- गौरवशाली, वैभवशाली भारत के निर्माण में मप्र देगा अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान
- केंद्रीय बजट के प्रावधानों से मप्र के विकास के लिए अधिकतम सहयोग लें
- शुरू होगा फसल पैटर्न में बदलाव, मालियों के प्रशिक्षण की होगी व्यवस्था
- मप्र में चारे को काटकर ब्लॉक बनाने की तकनीक को किया जाएगा प्रोत्साहित
- नर्मदा नदी के दोनों ओर पांच किमी की पट्टी पर विकसित होगी प्राकृतिक खेती
- नरवाई जलाने की प्रथा पर नियंत्रण के लिए होंगे विशेष प्रयास
- गोबर से सीएनजी उत्पादन के लिए जबलपुर में स्थापित होगा प्लांट

भोपाल। संवाददाता

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत केंद्रीय बजट अमृत काल का बजट है। यह प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का समय है। टीम मध्यप्रदेश बिना एक क्षण गवाए, प्रदेश के विकास और उन्नति के लिए निरंतर कार्य करें। गौरवशाली, वैभवशाली भारत के निर्माण में मध्यप्रदेश अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देगा। उन्होंने कहा कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट से, राज्य सरकार जिन-जिन गतिविधियों में लाभ ले सकती है, उसकी प्रत्येक विभाग व्यवहारिक कार्य-योजना बनाए। आवास, शहरी अधोसंरचना, कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्यम, औद्योगिक विकास, सड़कों के निर्माण, जल जीवन मिशन के लिए केन्द्रीय बजट में किए गए प्रावधानों का अध्ययन कर प्रदेश के लिए अधिकतम सहयोग प्राप्त किया जाए। किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि कृषि का विविधीकरण, मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहन और प्राकृतिक तथा जैविक खेती राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्रि-परिषद के जिन-जिन सदस्यों के पास खेती है, वे अपने खेत में प्राकृतिक खेती का मॉडल फॉर्म विकसित करें। इससे लोग प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित होंगे और धरती का स्वास्थ्य सुधारने में मदद मिलेगी। नर्मदा नदी के दोनों ओर पांच किमी की पट्टी पर प्राकृतिक खेती को विकसित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में फसल पैटर्न के बदलाव का कार्य खरीफ की फसलों के साथ आरंभ कर दिया जाएगा। नरवाई जलाने की प्रथा पर नियंत्रण के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे, इसके लिए किसानों को किराए पर मशीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जा रही है।

कृषि विवि को जोड़कर बनाई जाए रणनीति

उद्यानिकी की खेती में निर्धारित 22 उत्पाद का मैकेनिज्म विभिन्न जिलों के अधिकारियों तथा उत्पादकों के साथ तय किया जाए। उद्यानिकी उत्पाद, उनके गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग, मार्केटिंग और ब्राण्डिंग के लिए सम्पूर्णता में रणनीति बनाना और उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है। मधुमक्खी पालन को उन्हीं जिलों में प्रोत्साहित किया जाए जहां फूलों की खेती या फूलों वाली फसलें अधिक होती हैं। उद्यानिकी सहित पॉली हाउस, नर्सरी, प्राकृतिक खेती आदि के लिए दक्ष व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में मालियों के प्रशिक्षण के लिए विशेष व्यवस्था की जाना आवश्यक है। इस दिशा में कृषि विश्वविद्यालयों को जोड़कर रणनीति बनाई जाए।

जबलपुर में गोबर से बनेगी सीएनजी

पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि गोबर से सीएनजी उत्पादन के प्लांट के लिए जबलपुर को चिन्हित किया गया है। बनारस में संचालित प्लांट का निरीक्षण करने जबलपुर से टीम भेजकर तत्काल प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। हरे चारे को काटकर ब्लॉक बनाने की तकनीक को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सीएम ने कम राशि में संचालित होने वाले बकरी और मुर्गी पालन जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताई। मछली पालन में पुश्तैनी और परम्परागत रूप से कार्य कर रहे लोगों को सहकारिता गतिविधियों में प्रोत्साहित किया जाए। देश के जिन राज्यों में मछली पालन आधुनिकतम तरीकों से किया जा रहा है, उन राज्यों में प्रदेश के मछली पालकों के अध्ययन दल को भेजा जाए।

किसान ने गेहूं की खेती छोड़कर बोया चना,फसल विविधीकरण के लिए की तारीफ

चने के खेत में पहुंचे कृषि मंत्री, खेत में लगाई चौपाल

हरदा। संवाददाता

मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक किसान के खेत में पहुंचकर फसल विविधीकरण के लिए उसकी तारीफ की। किसान ने गेहूं छोड़कर चने की खेती की हुई है। इसके बाद कृषि मंत्री ने फसल बदल-बदलकर खेती करने वाले किसानों की तारीफकी। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से लागत भी कम लगेगी फसल अच्छी होगी। बाजार में कीमत भी किसानों को ठीक मिलेगी। दरअसल, इन दिनों केंद्र सरकार भी फसल विविधीकरण पर काफी जोर दे रहे है। वो चाहती है कि किसान धान और गेहूं की खेती कम करके दलहनी और तिलहनी फसलों की ओर आकर्षित हों। क्योंकि अभी इन दोनों में भारत आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में सरकार द्वारा की जा रही अपील का असर देखने के लिए पटेल अचानक हरदा के एक किसान के खेत में पहुंच गए और वहीं पर खेत चौपाल लगा दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों भाइयों से लगातार अपील की है कि वे फसल विविधीकरण अपनाएं। इसी अपील का जायजा लेने कमल पटेल हरदा जिले के ग्राम सिरकंबा मे किसान गोकुल करोड़े के खेत पर पहुंचे।

22 एकड़ में 22 लाख की फसल

किसान गोकुल करोड़े ने इस बार सरकार की अपील का ध्यान रखते हुए अपने खेत में गेहूं की बजाय डालर चना बोया है। गोकुल की फसल खेत में लहलहा रही है। गोकुल ने 22 एकड़ में चना बोया है। इसके पहले वे गेहूं की फसल लिया करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने सरकार की अपील और कृषि मंत्री के सुझावों को मानते हुए चना बोया। एक एकड़ में एक लाख की फसल इस इस बार होने का अनुमान है। यानी कि 22 एकड़ में 22 लाख की फसल।

गेहूं और चने का एमएसपी

किसान ने इस बात को स्वीकारा कि अगर गेहूं की फसल लेते तो उन्हें 4 बार पानी देना होता, मेहनत भी ज्यादा करना पड़ती और लागत ज्यादा लगती, आमदनी कम होती। रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5230 रुपए प्रति क्विंटल है। जबकि गेहूं का एमएसपी 2015 रुपए होगी।

कम लागत का दावा

कृषि मंत्री ने खेत चौपाल पर किसान गोकुल करोड़े को बधाई देते हुए किसान भाइयों से फसल विविधीकरण पर जोर देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से लागत भी कम होगी, फसल अच्छी होगी, कीमत अच्छी मिलेगी और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। ऐसा करने से ही खेती लाभकारी काम बनेगा। आत्मनिर्भर किसान होगा तो आत्मनिर्भर भारत का भी सपना साकार होगा।

मिशन-2023-24: कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष में भाजपा का संगठन पर्व

भाजपा को मजबूत करेंगे 'त्रिदेव'

अब हितग्राहियों को संपर्क के माध्यम से पार्टी से लगातार जोड़े रखने पर फोकस करेगी

मध्यप्रदेश में भाजपा का 15 दिवसीय बूथ विस्तारक अभियान सुर्खियों में है। अभियान के माध्यम से भाजपा ने अपने बूथ को मजबूत किया है। उन कार्यकर्ताओं तक पहुंचने की कवायद है, जिन्हें सिर्फ चुनाव के समय मतदान केंद्र पर ड्यूटी के दौरान ही याद किया जाता है। भाजपा का बूथ विस्तारक अभियान सिर्फ इसी लक्ष्य तक सीमित रहा या फिर इसके पीछे पार्टी का कोई अलग एजेंडा भी था। इसी की पड़ताल करती जागत गांव हमार की यह रिपोर्ट।

भोपाल। यह नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की भाजपा है। वरना कौन सी ऐसी पार्टी है, जो बिना किसी चुनाव समय के बूथ स्तर पर जाने में लाखों घंटे बिताए। पर अब बूथ विस्तारक अभियान समाप्त होने के बाद राजनैतिक विश्लेषकों के समझ में आ रहा है कि इसके माध्यम से भाजपा ने राजनैतिक दल में अंत्योदय की भूमिका में रहे बूथ समिति तक पहुंचकर उनसे मजबूत बंध बनाने का काम साध लिया है। उन्हें डिजिटल प्लेटफार्म पर संग्रहित कर पार्टी के राष्ट्रीय हाईकमान से लेकर स्थानीय हाईकमान के एक क्लिक पर लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल, भाजपा अपने पितृ पुरुष का जन्म शताब्दी वर्ष को संगठन पर्व के रूप में मना रही है। एक वर्ष तक चलने वाले इस पर्व में भाजपा खुद को और सशक्त बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। भाजाप ने संवाद और संपर्क के माध्यम से निचले कार्यकर्ता और सरकार से लाभांवित हितग्राहियों तक पहुंचने का पूरा खाका तैयार किया है। पहले चरण में भाजपा ने बूथ स्तर तक पहुंचकर कार्यकर्ताओं की टीम को सशक्त किया। जल्द ही हितग्राहियों को भी संपर्क के माध्यम से पार्टी से लगातार जोड़े रखने पर फोकस किया जाएगा।

बूथ विस्तार अभियान के दौरान भोपाल के नन्ना जी से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मिले। उनका तिलक लगाकर सम्मान किया और आशीर्वाद लिया। नन्ना जी मप्र में एक मजबूत भाजपा की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई है।

पार्टी के अंत्योदय तक सबसे पहले

भाजपा के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को पार्टी ने मप्र में पार्टी में भी आत्मसात किया। तभी राजनैतिक दल की सबसे निचली इकाई बूथ समिति, जिसको सिर्फ चुनाव के समय याद किया जाता है, उस तक सबसे पहले पहुंची। यही नहीं, भाजपा के प्रदेश के सभी दिग्गज नेताओं सहित राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भी बूथ तक भेजकर नेता कार्यकर्ता एक समान का संदेश दिया। भाजपा हमेशा नए लक्ष्य लेकर काम करती है और जब लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो उसके कारणों की तह तक जाकर उन कमियों को दूर करने में जुट जाती है। भाजपा का बूथ विस्तारक अभियान भी ऐसा ही रहा।

2018 में लगा था झटका

वर्ष 2018 का विधानसभा चुनाव.. भाजपा का व्यापक दृष्टि पत्र और नारा अबकी बार, 200 पार...पर जब परिणाम आया तो सभी हैरान थे। पार्टी में किसी को भी ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। विधानसभा सीटों का लक्ष्य बहुत पीछे छूट ही गया था..उससे भी ज्यादा चिंताजनक था भाजपा का वोट प्रतिशत 4 फीसदी कम हो जाना...कारणों को तलाशने के दौर शुरू हुआ। तब एक बड़ा कारण बूथ पर कमजोर प्रदर्शन भी सामने आया। तभी से भाजपा बूथ को लेकर एक महाअभियान की रणनीति पर काम कर रही थी। कोरोना के दुष्प्रभाव निकल जाने के बाद भाजपा अब इस अभियान पर जुट गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद वीडी शर्मा के नेतृत्व में पार्टी ने इस अभियान को अपने हाथ में लिया और बूथ तक पहुंचने के संकल्प को साधा।

पहले चरण में भाजपा ने बूथ स्तर तक पहुंचकर कार्यकर्ताओं की टीम को सशक्त किया

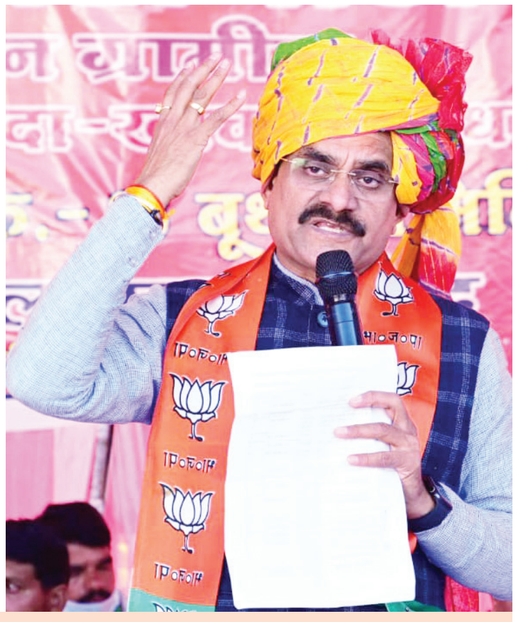

बुजुर्गों का सम्मान

भाजपा अपने बूथ विस्तारक अभियान में जनसंघ से जुड़े पार्टी के बुजुर्ग नेताओं का सम्मान भी किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस अभियान में जहां भी गए, वहां बुजुर्ग कार्यकर्ताओं का सम्मान किया।

त्रिदेव

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बूथ पर काम करने वाले बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बीएलओ को त्रिदेव की संज्ञा दी, जो मजबूती से पार्टी के लिए बूथ पर काम करता है, संघर्ष करता है।

संपदा कार्ड

भाजपा बूथ समिति को संपदा आई कार्ड भी देने जा रही है। संपदा कार्ड में 'स' से सम्मान, 'प' से पहचान और 'दा' से दायित्व जोड़ा गया। यह भाजपा का डिजिटलाइजेशन की तरफ बड़ा कदम है।

डिजिटल वार रूम

भाजपा के इस महाभियान की माइक्रो लेवल पर मानिटरिंग डिजिटल वार रूम में की गई। अभियान में पार्टी के सचिव रजनीश अग्रवाल, रोजगार बोर्ड के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा, आईटी सेल के संयोजक अमन शुक्ला, गौरव विश्वकर्मा और अभिषेक शर्मा के नेतृत्व में टीम 24 घंटे वार रूम में जुटी रही।

भाव-विभोर करने वाले नजारे

मुझे सब कुछ मिल गया

भाजपा के इस अभियान में भावविभोर कर देने वाले नजारे देखने को मिल रहे हैं, के खाचरोद के एक बूथ पर जब भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा 81 वर्षीय बुजुर्ग कार्यकर्ता पूरनदास बैरागी से मिले। बैरागी भावविभोर हो गए और वे अपनी भावना जाहिर करने से नहीं चूके। उन्होंने अपने जीवन काल में पार्टी को दिए गए समय का जिक्र करते हुए कहा कि मैं जब पार्टी के काम से जाता था, लोगों से मिलता था, तो वो मुझसे पूछते थे कि तुम्हें तन्खा मिलती है क्या? मैं कहता था, तन्खा नहीं मिलती, पर ये सारी मेहनत मेरे खाते में लिखाती जा रही है। इतने सालों में जो मेरे खाते में आया था, आज वो सब कुछ मुझे एक ही बार में मिल गया।

- 20 लाख घंटे का समय दान
- 65 हजार बूथों तक पहुंचने का लक्ष्य
- बूथ समितियों का डिजिटलाइजेशन
- सभी नेताओं को बूथ तक पहुंचाया
- बूथ पर दिन-रात काम किया
- रजिस्टर पर पंजीयन भी किया
- एप पर पंजीयन कराया गया
- रियल टाइम पंजीकरण हुआ
- लाइव फोटो अपडेट ओटीपी के माध्यम से
- भाजपा को 2018 में मिले 41 फीसदी वोट
- 2013 के मुकाबले करीब 4 फीसदी वोट का नुकसान
- 2023 के चुनाव में रखा है 51 फीसदी वोट का लक्ष्य

बूथ विस्तारक इतिहास का सबसे बड़ा अभियान

कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष पर भाजपा ने 20 जनवरी से बूथ विस्तारक योजना चालू की। इसमें पांच फरवरी तक मध्य प्रदेश के 65 हजार बूथों पर बूथ विस्तारकों को भेजा गया। राजनीतिक इतिहास में भाजपा इसे सबसे बड़ा अभियान बता रही है। अभियान के लिए इंदौर और भोपाल के कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया। बूथ विस्तारक बूथों पर प्रवास कर केंद्र की जानकारी एकत्रित की गई। उनके साथ रहने वाले आईटी संचालक इसे संगठन एप में अपलोड किया गया। इसकी मॉनीटरिंग के लिए प्रदेश कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां से कार्यकर्ताओं को टेक्निकल सपोर्ट दिया गया।

बैठक में बना था मास्टर प्लान

कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशताब्दी वर्ष समारोह पर 16 जनवरी को भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक बैठक हुई थी। इसमें संगठन को मजबूती देने के लिए मास्टर प्लान तैयार हुआ था। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा की मौजूदगी में निर्णय हुआ था कि पार्टी बूथ विस्तारक योजना चलाएगी। ताकि 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को फायदा मिले।

15 दिनों में 100 घंटे काम

बूथ विस्तारक योजना के तहत संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन 10 घंटे यानी इन 15 दिनों में 100 घंटे का श्रम किया। इस दौरान 9 हजार शक्ति केंद्रों पर 20 हजारा विस्तारक पहुंचे। खास बात यह है कि विस्तारक की भूमिका सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्रियों के साथ ही अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। जिन्हें बूथ विस्तारक की जिम्मेदारी दी गई थी।

लक्ष्य-65 हजार बूथ

बूथ विस्तारक योजना के तहत 15 दिन में 65 हजार बूथों तक संगठन को मजबूत करने का लक्ष्य था।

अभियान बना रोल मॉडल

कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष को भाजपा पार्टी के सुदृढ़ीकरण और विस्तार के लिए चुना। अभी तक पार्टी नहीं पहुंची थी, वहां पहुंचने की योजना इस संगठन यज्ञ के माध्यम से पहुंची। यह साधारण नहीं, ऐतिहासिक अभियान था। यह अभियान पूरे देश में रोल मॉडल बन गया है। अभियान के दौरान संगठन को गुणात्मक और संख्यात्मक रूप से मजबूत बनाते हुए 10 प्रतिशत वोट बढ़ाने का लक्ष्य सामने था।

पहले देश, फिर दल, यह हमेशा हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए भाजपा का मंत्र रहा है। सभी पन्ना प्रमुखों को अपने पन्ना में मौजूद प्रत्येक सदस्य को जानने का प्रयास करना चाहिए और चुनाव हो या न हो, उनके साथ अपने परिवार की तरह व्यवहार करना चाहिए। इस अभियान से पार्टी को मजबूती तो मिलेगी ही साथ ही भारत भी मजबूत होगा।
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

कुशाभाऊ ठाकरे ने विपरीत परिस्थितियों और अभावों के बीच पार्टी संगठन को खड़ा कर पार्टी के विचार को हर बूथ तक पहुंचाया। उन्होंने अपना पूरा जीवन संगठन के लिए होम कर दिया। इसलिए बूथ विस्तारक योजना संगठन के विस्तार और सशक्तीकरण के लिए अहम योजना तो है ही, यह योजना ठाकरे को हमारी ओर से सच्ची श्रद्धांजलि है।
अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

भाजपा अगर आज देश का सबसे बड़ा दल बना है, तो इसके पीछे लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम और बलिदान है। पर्दे के पीछे रहकर विचारधारा के लिए बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के कारण ही हम मजबूत हैं। आज पंच और पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक ऐसा कोई पद नहीं है, जहां भाजपा नहीं है। गरीब मां का बेटा पीएम है।
जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

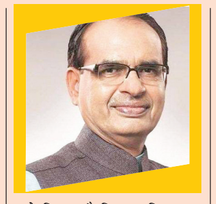

मुझे विश्वास है कि बूथ विस्तारक योजना तथा उसके एप संगठन से अधिक युवा जुड़कर राष्ट्र व जनसेवा में अपना योगदान देंगे। जन-जन की भागीदारी से ही राष्ट्र व समाज की उन्नति के संकल्पों की सिद्धि होगी। डिजिटल एप के माध्यम से प्रत्येक कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ताओं का डेटा रहेगा। प्रदेश में अभियान का उद्देश्य कार्यकर्ता से सीधा संवाद था।
शिवराज सिंह चौहान, सीएम

कुशाभाऊ ठाकरे के जन्मशताब्दी वर्ष को हम संगठन पर्व के रूप में मना रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत काफी अच्छा काम हुआ है और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ। अभियान में मुख्यमंत्री, मंत्री संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। हमारी पार्टी कैडर बेस पार्टी है, जो लगातार संगठनात्मक कार्य करती है।
वीडी शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष, भाजपा

कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशताब्दी वर्ष में संगठन पर्व के तहत पार्टी का हर पदाधिकारी, कार्यकर्ता देश और प्रदेश के सभी बूथों को सशक्त और डिजिटल बनाने के लिए संकल्पित हैं। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर हम प्रत्येक बूथ पर 51 प्रतिशत वोट शेयर का लक्ष्य हासिल करेंगे। भाजपा कार्यकर्ता आधारित दल है।
नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री

कुशाभाऊ एक श्रेष्ठ संगठक थे, जिनके शरीर का कण-कण संगठन के लिए समर्पित था। ठाकरे ने अपनी कुशलता, नेतृत्व क्षमता एवं दीर्घ अनुभव से संगठन का विस्तार एवं समय दान करते हुए समर्पित कार्यकर्ताओं की एक पूरी पीढ़ी तैयार की। स्वावलंबी मंडल व सक्षम बूथ हमारा लक्ष्य है। बूथ विस्तारक अभियान सर्वश्रेष्ठ अभियान है।
पी मुरलीधर राव, प्रदेश प्रभारी

बूथ विस्तारक योजना के परिणाम बहुत उत्साहवर्धक रहे। पार्टी के 20 हजार से अधिक विस्तारकों ने, हमारे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश सरकार के मंत्री, संगठन पदाधिकारियों ने काम किया है। उनकी सक्रियता से पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है। बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि इस योजना में कई अद्भुत काम हुए हैं।
सुहास भगत, प्रदेश संगठन महामंत्री

बूथ व पन्ना समितियां पार्टी की असल पूंजी हैं। इन्हीं समितियों के दम पर हम शासन की योजनाओं से आमजन को लाभान्वित कराएंगे, आपदा के समय पीड़ितों की सेवा करेंगे। चुनावों में प्रत्येक बूथ पर कमल खिलाएंगे। भाजपा आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इसे कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम से, खून-पसीने से सींचा है।
शिव प्रकाश, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री

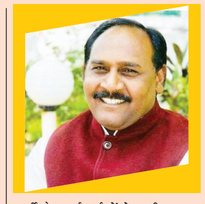

पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभी तक जितने भी अभियान हाथ में लिए हैं उन सभी में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। ठाकरे के जन्मशताब्दी वर्ष में शुरू की गई बूथ विस्तारक योजना राजनीतिक इतिहास में अभी तक का पार्टी का सबसे बड़ा अभियान है। अभियान के माध्यम से हमारे बूथ डिजिटल होने के साथ ही संगठन का कार्य विस्तार भी हुआ।
लाल सिंह आर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति मोर्चा

अभियान के दौरान बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक न सिर्फ इससे सीधा संवाद हुआ, बल्कि हमें बूथ तक अपनी पार्टी की स्थिति की सही सही जानकारी भी प्राप्त हुई। बूथ विस्तारक के साथ इस अभियान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एप विस्तारक रहा। जहां बेहद संजीदगी से काम किया गया। 15 दिन हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए अहम रहे।
राजेंद्र शुक्ल, विधायक, भाजपा

भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो नौजवानों को साथ लेकर अपने वरिष्ठजनों को भी कभी विस्मृत नहीं करती। हम सिर्फ चुनाव में सक्रिय हों ऐसा नहीं, हमारे लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा से अधिक सामाजिक दायित्वों का निर्वहन है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम करते हैं।
भरत लाल पांडेय
पूर्व मंडल अध्यक्ष

देश में प्रासंगिकता खोती शंकर गाय

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, शिवपुरी

श्वेत क्रांति के आगाज के साथ देश में एक नारा दिया गया था कि देशी गाय से शंकर गाय, अधिक दूध और अधिक आय, लेकिन शंकर गाय अपने आप को भारतीय जलवायु के अनुकूल ढाल पाने में असमर्थ ही सिद्ध हो रही हैं। क्रॉसब्रीड गाय बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। इनमें रोगों और बीमारियों की समस्या भारतीय स्वदेशी गायों की तुलना में काफी ज्यादा है। मानव स्वास्थ्य पर इनके दूध से पढ़ने वाले दुष्प्रभाव को लेकर भी पूरी दुनियां में बहस और शोध जारी हैं। श्वेत क्रांति के आगाज के समय जो नारा दिया गया था उसमें अब बदलाव की जरूरत महसूस की जाने लगी है। इसलिए अब उस नारे को बदलकर विदेशी (शंकर/क्रॉसब्रीड) गाय से भारतीय गाय, अधिक टिकाऊ और अधिक आय किए जाने की जरूरत है।

देखने में आ रहा है कि शंकर/क्रॉसब्रीड गाय अपनी प्रासंगिकता खो चुकी हैं। भारत में श्वेत क्रांति के आगाज के दौरान देश में शंकर अर्थात क्रॉस ब्रीड गायों का आगमन हुआ। विदेशी नस्ल के सांड़ों से भारतीय नस्ल की गायों को क्रॉस कराकर शंकर गाय की नस्लों को तैयार किया गया। इसके बाद देश में जर्सी, हॉल्स्टीन-फ्रीजियन, ब्राउन स्विस, करण स्विस, फ्रीजवाल जैसी क्रॉस ब्रीड गाय विकसित की गई, जो कि शंकर गायों के रूप में पहचानी जाने लगीं। यह गाय भारतीय गायों की तुलना में ज्यादा दूध देने की क्षमता रखती थी। इस कारण कुछ ही वर्षों में पूरे देश में इन गायों का पालन किया जाने लगा। लेकिन पिछले एक दशक के दौरान आम जागरूक लोगों से लेकर पशुपालन से जुड़े वैज्ञानिकों एवं जानकारों में शंकर गायों द्वारा पैदा किए जा रहे ए-1 दूध से मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर बहस जारी है। कई शोध बताते हैं कि क्रॉस ब्रीड गायों का दूध मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी भारतीय गाय पूज्यनीय है। हिंदू पूजा-पाठ में गाय का दूध, घी, दही, यहां तक कि गाय के गोबर से बने उपलों का भी महत्व है। हिंदू संस्कृति में स्वदेशी भारतीय गायों का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार गाय, गाय का दूध (गौडुग्धा), घी (गौघृत), मूत्र (गौमूत्र), गोबर (गौमय) का यज्ञ अनुष्ठान में महत्वपूर्ण स्थान है बिना इसके यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय स्वदेशी गाय को संरक्षित करके संरक्षण देने की महती जरूरत है। परंतु इससे पहले स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ए-1 दूध पैदा करने वाली क्रॉसब्रीड गायों को देश से हटाना होगा। भारतीय स्वदेशी गायों में दुग्ध उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाना होगा जिससे क्रॉसब्रीड गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता को टक्कर दी जा सके। सर्वप्रथम भारत में इ पीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर द्वारा 1910 में पहली बार आयरशायर और हरियाना एवं रेडसिंधी नस्ल के साथ क्रॉस कराया गया था। भारतीय कृषि शोध संस्थान, पूसा, बिहार में 1920 में साहीवाल गाय के साथ क्रॉस ब्रीडिंग की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार द्वारा 1964-65 में गहन पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिसमें उन्नत पशुपालन तकनीकियों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में आपरेशन लड की शुभारंभ किया गया, जो कि श्वेत क्रांति का वाहक बना। गाय के दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने विदेशी सांड़ों और उनके वीर्य का उपयोग करके क्रॉस-ब्रीडिंग का सहारा लिया। इसके बाद यूरोपियन देशों से विदेशी साड़ों का हिमीकृत वीर्य मंगाकर स्वदेशी गायों को गर्भित कराया जाने लगा। कुछ ही सालों में देश के हर क्षेत्र में क्रॉसब्रीड गायों का बोलबाला बढ़ता गया और स्वदेशी भारतीय गाय बेकदरी का शिकार होकर दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर होती चली गई। ऊपर से रही-सही कसर खेती में मशीनीकरण के आ जाने से पूरी हो गई। जिसके कारण स्वदेशी भारतीय गाय के बैल-बछड़ें अनुपयोगी हो गए। ऑपरेशन लड कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश में विदेशी साड़ों के सीमन से कृत्रिम गर्भाधान अभियान चलाया गया। जिसके चलते भारतीय गायों की नस्लें साहीवाल, गिर, थारपारकर, रेडसिंधी, हरियाणा, कांकरेच, राठी, देवनी आदि का जर्सी, हॉलीस्टीन फ्रीजन, यार्कसायर आदि विदेशी नस्लें के सांड़ों के सीमन से गर्भाधान कराकर नस्ल में बदलाव किए गए। अब

देखने में आ रहा है कि देश में क्रॉसब्रीड गायों के पालन के लंबे अनुभव के बाद इन गायों में कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। शंकर गाय रोगों एवं बीमारियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। क्रॉस ब्रीड गायों में थनैला बीमारी की गंभीर समस्या देखी जा रही है। इन नस्लों में बांझपन, बार-बार गर्मी पर आना तथा गर्भ नहीं ठहरने का प्रतिशत बहुत अधिक है। इसके चलते इन गायों के इलाज पर पशुपालकों को एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। इनका पालन करना महंगा सौदा तो साबित हो ही रहा है अपितु इन रोगों के इलाज के उपरांत भी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। आज भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए देशी गाय के गोबर एवं मूत्र की उपयोगिता बताई जा रही है। गत माह एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसके फायदे गिना चुके हैं। पद्मश्री सुभाष पालेकर के अनुसार एक स्वदेशी भारतीय गाय से 30 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती किया जाना संभव है। स्वदेशी गायों की नस्लें कठिनतम जलवायु परिस्थितियों का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। यह गाय बीमारियों के प्रति भी अधिक संवेदनशील होती हैं, जो कि भारत की उष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय जलवायु को सहन करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। भारत में गायों की 27 पंजीकृत नस्लें हैं जिनमें कई अच्छी दुग्ध उत्पादक नस्लें भी शामिल हैं। जिनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता क्रॉसब्रीड गायों से कमतर नहीं हैं। भारत की स्वदेशी गायों की नस्लों में साहीवाल, गिर, रैडसिंधी, राठी, थारपारकर आदि अच्छी दुग्ध उत्पादक नस्लें हैं। देश की ये स्वदेशी नस्लें पूरी तरह से भारतीय जलवायु के अनुकूल हैं। यह नस्लें रोग एवं बीमारियों के प्रति भी काफी सहनशील हैं और इनका दूध ए-2 दूध की श्रेणी में आता है। इतना ही नहीं, बल्कि भारतीय स्वदेशी गायों की नस्लों का दूध, घी से लेकर गोबर और मूत्र तक काफी उपयोगी है। भारतीय गायों की उपयोगिता और टिकाऊपन की बानगी इससे समझी जा सकती है कि ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देश हमारी स्वदेशी नस्लों को अपने देश ले जाकर जर्मप्लाज्म को संरक्षित करके अपने यहां नस्लें विकसित कर रहे हैं। पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा ही क्रॉसब्रीड गायों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया गया था। आज भारत सरकार फिर से भारतीय स्वदेशी गायों को आगे लेकर आ रही है। इसके लिए भारत सरकार स्वदेशी नस्लों के संरक्षण, सवर्धन और उन्नयन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन से लेकर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग तक का गठन कर चुकी है। स्वदेशी गायों के संरक्षण के लिए दो राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्रों को जिम्मेदारी दी गई है, जो कि मप्र के इटारसी और आध्रप्रदेश के चिंतलदेवी में खोले गए हैं। केंद्र से लेकर प्रदेश सरकारों की नीतियों को देखते हुए क्या अब समय आ गया है कि धीरे-धीरे ही सही, परंतु क्रॉसब्रीड गायों को देश से हटाया जाए। शुरुआत में गांवों, शहरों, खेतों एवं जंगलों में घूमने वाले क्रॉसब्रीड गायों खासकर साड़ों को पहले हटाकर की जानी चाहिए। वैसे भी यह भारतीय परंपराओं के अनुरूप देशी गौवंश की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिए इनको हटाने के विकल्प तलाशे जाने की जरूरत है जिससे गांव-खेतों, सड़कों एवं शहरों में घूमने वाले आवारा क्रॉसब्रीड सांड अनाधिकृत रूप से प्रजनन न कर सकें। आज जितना स्वदेशी दुधारू गायों के संरक्षण की जरूरत है उतना ही क्रॉसब्रीड गायों को हटाए जाने की है।

समाज को चाहिए संविधान की शिक्षा

भारतीय समाज में राजनीतिक विकास की गति और चिंतन में निरंतर विकास और बदलाव हुए हैं, पर सामाजिक सुधारों में उतनी सकारात्मकता नहीं दिखाई पड़ रही। सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र भाईचारे में वृद्धि नहीं कर पा रहा। संविधान कानून के विद्यार्थियों या कोर्ट-कचहरी, खासकर शासन-प्रशासन के क्रिया कलापों तक सीमित है, जबकि समाज में जो कानून लोगों के व्यवहारों को संचालित करता है, वे रीति-रिवाज, प्रथाएं या परंपराएं हैं। क्या गांवों में सांविधानिक मूल्यों से किसी का वास्ता है? क्या कहीं स्कूलों के पाठ्यक्रम में संविधान का सार पढ़ाया जाता है।

सिर्फ राजनीतिशास्त्र या विधिशास्त्र के अध्येताओं के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन शैली में सुधार की दृष्टि से हर विषय और हर अनुशासन को सांविधानिक शिक्षा का अनुशीलन करना अपेक्षित है। अशिक्षितों या अल्प शिक्षितों को भी संविधान की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके अभाव में अलोकतांत्रिक, सामंती और असभ्य आचरण देश के कई हिस्सों में दिखाई पड़ रहा है। गणतंत्र दिवस के समय ही राजस्थान के छड़ी गांव की खबर आई, जहां से दलित समाज के एक दूल्हे श्रीराम मेघवाल की घोड़ी पर चढ़कर बारात निकलने पर खुशी का माहौल था, क्योंकि उस गांव में पहली बार ऐसा हुआ। आजादी के इतने वर्षों के बाद एक दलित दूल्हे के घोड़ी पर बैठने पर समाज की खुशी क्या बताती है। मध्य प्रदेश के गनियारी गांव में तो पहली बार दलित दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा, तो सवर्ण समाज के लोगों ने बारात पर हमला कर दिया। 30 जनवरी को राजस्थान में ही चुरू के एक गांव में एक दलित को लाठी और रस्सी से इतना पीटा गया कि वह बेहोश हो गया। मानवाधिकार आयोग ने घटना का संज्ञान लिया। डॉ. आंबेडकर सामाजिक भेद-भाव, जाति-क्रूरता और धार्मिक अनुदारता के भुक्त-भोगी थे। उन्हें ऐसी आशंका थी, इसलिए संविधान की निर्माण-प्रक्रिया में वह समता, बंधुत्व और स्वतंत्रता के मूल्यों की बात कर रहे थे। क्या समाज सांविधानिक मूल्यों के अनुरूप विकसित हो रहा है। क्या हम सामाजिक दृष्टि से आदर्श लोकतंत्र में जी रहे हैं। सुभाष कश्यप कहते हैं कि हमारे गणतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती सांविधानिक निरक्षरता है। संविधान के बारे में लोगों में शिक्षा और चेतना का अभाव है। मैं समझता हूं कि सांविधानिक शिक्षा देश में अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि लोग लोकतांत्रिक मूल्यों एवं नागरिक कर्तव्यों के बारे में जान सकें।...अगर संविधान के बारे में पता नहीं है, तो उसका पालन कैसे होगा। इसलिए चाहे कोई किसी भी शाखा की पढ़ाई करे, सबके लिए संविधान की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। इसमें इतना और जोड़ लेना चाहिए कि हर स्तर की प्रशासनिक सेवा में, स्कूल-कॉलेज की प्रवेश-परीक्षा में, टीचर्स, प्रोफेसर के प्रशिक्षण में सांविधानिक शिक्षा का एक प्रश्नपत्र पास करना अनिवार्य होना चाहिए। ग्राम सचिवों और प्रधानों को संविधान शिक्षा की परीक्षा पास करनी चाहिए। नहीं तो ग्रामीण समाज में सामंती अनुदारता बनी रहेगी। विगत अक्टूबर में हनुमानगढ़ में दलित की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दलित से प्रेम विवाह कर लेने वाली युवती को उसी के परिजनों ने फांसी पर लटका दिया। प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि वह सांविधानिक कानूनों का पालन करे, पर उत्तर प्रदेश की पुलिस की भूमिका तो हाथरस की दलित युवती की हत्या व बलात्कार के मामले में संदिग्ध रही, जहां परिवार की अनदेखी कर उसका दाह-संस्कार कर दिया गया था। विगत दिसंबर में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से खबर आई, पेशाब पीने पर मजबूर करने वाला दारोगा निलंबित। जयपुर के कोटपूतली कस्बे में दलित दूल्हे के घोड़ी चढ़ने पर आपत्ति जताई गई और पुलिस की मौजूदगी में बारात पर पत्थर फेंके गए। समाज के उच्च-वर्णीय सामंती मूल्य और लोकतांत्रिक सांविधानिक मूल्य रोजमर्रा के व्यावहारिक जीवन में तालमेल कम दिखाते हैं, टकराते अधिक नजर आते हैं। इसी कारण विगत नवंबर में उच्चतम न्यायालय को कहना पड़ा कि जाति से प्रेरित हिंसा की घटनाओं से पता चलता है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी जातिवाद खत्म नहीं हुआ। उत्तराखंड में चंपावत जिले के एक विद्यालय में भोजनमाता के बहिष्कार की कहानी की जड़ में यही जातिवाद था। उस स्कूल में छात्रों के लिए भोजन बनाने वाली सुनीता देवी को निचली जाति का बताकर कथित ऊंची जाति के छात्रों ने खाना खाने से मना किया। नतीजतन शिक्षा अधिकारी ने उस महिला को नौकरी से बाहर कर दिया था। उसकी प्रतिक्रिया में दलित छात्रों ने सामूहिक रूप से कहा कि हमें हमारी वही भोजनमाता चाहिए, हम किसी गैर-दलित रसोइए के हाथ का खाना नहीं खाएंगे।

बजट 2022: ग्रोथ का बजट

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव करीब हैं, इसलिए यह आम सोच थी कि बजट लोकलुभावन होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सोच को गलत साबित किया है। बजट का फोकस सरकारी खर्च बढ़ाकर आर्थिक विकास दर तेज करने पर है, जिसकी जरूरत भी थी। इसलिए यह ग्रोथ का बजट है, बोल्ड बजट है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023 में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 35.4 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। यह बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन इससे महंगाई दर बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2023 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.4 फीसदी रखा है, जो इससे पिछले साल में 6.8 फीसदी रहा। यह भी ठीक है। अभी आर्थिक रिकवरी को मजबूत बनाने की जरूरत है, इसलिए आने वाले वर्षों में राजकोषीय घाटे को धीरे-धीरे कम किया जा सकता है। पीएम गति शक्ति के जरिये वित्त मंत्री ने इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने का एलान किया। यह भी अच्छा कदम है। सरकार कुछ समय से पीएलआई स्कीम के जरिये 14 क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दे रही है। यह आत्मनिर्भर भारत के अजेंडा के साथ निर्यात बढ़ाने में भी कारगर हुआ है। रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर भारत के अजेंडा को सरकार ने आगे बढ़ाया है। वित्त मंत्री ने बजट में क्रिप्टोकरंसी पर भी निवेशकों की उलझन दूर कर दी। उन्होंने इससे हुए मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा। वित्त वर्ष 2023 में रिजर्व बैंक डिजिटल करंसी लाएगा, इसका ऐलान भी निर्मला सीतारमण ने किया। इन दोनों बातों से लगता है कि सरकार ने क्रिप्टोकरंसी को एक एसेट तो मान लिया है, लेकिन वह इन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहती। पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया, वैसे, अगर इसमें राहत दी गई होती तो उससे खपत बढ़ाने में मदद मिलती। खासतौर पर यह देखते हुए कि हाल के वर्षों में मध्य वर्ग की आय में भी कमी आई है और आर्थिक असमानता भी बढ़ी है। यहां तक कि समृद्ध तबके को भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स पर सरचार्ज घटाकर राहत दी गई है। निम्न-मध्यम आय वर्ग के लिए हाउसिंग सेक्टर में सौगात दी गई है।

मप्र में 11 साल से हो रहा इंतजार, राजस्थान में लोग उठा रहे चंबल सफारी का लुत्फ,

शिवपुरी/श्योपुर। खेमराज मौर्य

मप्र की सीमा में पाली घाट पर वर्ष 2011 में तत्कालीन वन मंत्री ने किया था चंबल सफारी का शुभारंभ

इसे सिस्टम की हीलाहवाली कहे या फिर विभागीय अफसरों की उदासीनता कि चंबल नदी में जहां राजस्थान सीमा में लोग चंबल सफारी का लुत्फ उठा रहे है, वहीं मप्र के श्योपुर जिले की सीमा में चंबल सफारी शुरू होने का 11 सालों से इंतजार ही चल रहा है। यहां वर्ष 2011 में बड़े जोर-शोर के साथ तत्कालीन वनमंत्री ने चंबल सफारी का शुभारंभ किया था। शुभारंभ होने के बाद भी मप्र की सीमा में बोटिंग अभी तक भी शुरू नहीं हो पाई है। इससे ऐसा लग रहा है कि विभागीय अफसर शुभारंभ कराने के बाद बोटिंग शुरू करवाना भूल गए है। जिस कारण श्योपुर के सैलानियों को बोटिंग का लुत्फ लेने के लिए राजस्थान जाना पड़ रहा है।

उल्लेखनीय है कि चंबल नदी का श्योपुर के पाली घाट से उत्तरप्रदेश के चकरनगर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के अन्तर्गत आता है। 435 किलोमीटर लंबाई में फैले राष्ट्रीय चंबल घडियाल अभयारण्य के अंतर्गत श्योपुर जिले की सीमा में चंबल नदी में पर्यटकों को बोटिंग का लुत्फ प्रदान करने के लिए चंबल सफारी की प्लानिंग अभ्यारण्य प्रबंधन और मध्यप्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से की थी। इसके तहत श्योपुर के पाली घाट से रामेश्वर त्रिवेणी संगम तक चंबल सफारी में बोटिंग कराई जाने की कार्ययोजना थी। इस दौरान चार मोटर बोट चलाई जानी थी। इसके लिए 18 नवंबर 2011 को पाली घाट पर इसका शुभारंभ भी समारोहपूर्वक किया गया, जिसमें तत्कालीन वनमंत्री सरताज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, वहीं इको टूरिज्म व वनविभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। चंबल सफारी के शुभारंभ के दौरान तत्कालीन वनमंत्री और वन विभाग के तत्कालीन अफसरों ने बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन बड़े-बड़े दावो के बाद भी चंबल सफारी 11 साल का समय बीतने के बाद भी शुरू नहीं हो सकी है। इससे जाहिर हो रहा है कि तत्समय श्रेय लेने की होड़ में चंबल सफारी का शुभारंभ कर दिया और अब अफसर ही उसे भूल गए हैं।

राजस्थान सीमा में चल रही 11 मोटर बोट, श्योपुर से भी पहुंच रहे सैलानी

राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सीमा में जहां 11 साल से बोटिंग शुरू होने का इंतजार बना हुआ है। वहीं चंबल नदी के दूसरी पार राजस्थान की सीमा में स्थित चंबल अभ्यारण्य प्रबंधन द्वारा चंबल सफारी शुरू कर दी गई है। राजस्थान के अफसरों की माने तो पाली घाट पर पर्यटन को बढावा देने के लिए इसी साल से 11 मोटर बोट के जरिए चंबल सफारी का आनंद सैलानियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां दूर-दूर के सैलानी चंबल सफारी का लुत्फ लेने के लिए पहुंच रहे है। श्योपुर जिले के सैलानी भी चंबल में बोटिंग का आनंद देने के लिए राजस्थान के पाली घाट पर पहुंच रहे है।

राजस्व की भी लग रही चपत

श्योपुर जिले की सीमा में चंबल सफारी शुरू होने से जहां विभागीय अफसरों की उदासीनता उजागर हो रही है। वहीं मप्र शासन को राजस्व की चपत भी लग रही है। क्योंकि चंबल सफारी शुरू होने पर शासन को भी राजस्व की प्राप्ति होती। वर्तमान में श्योपुर जिले के लोग भी बोटिंग का लुत्फ लेने के लिए राजस्थान पहुंच रहे है, इसलिए राजस्थान सरकार का राजस्व बढ़ रहा है।

अभी कुछ दिन पहले ही प्रभार संभाला है, इसलिए जानकारी नहीं है कि पाली से रामेश्वर घाट तक चंबल सफारी अभी तक शुरू क्यों नहीं हो पाई। मगर इसकी जानकारी लेकर इस संबंध में कार्रवाई करेंगे।
एसआर दीक्षित
डीएफओ, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मुरैना

इसी साल से चंबल सफारी का विधिवत संचालन शुरू कर दिया है। सैलानियों के लिए 11 मोटर बोटों का संचालन किया जा रहा है। जहां निर्धारित शुल्क के साथ सैलानियों को चंबल की सैर करवाई जा रही है। यहां सभी जगह के सैलानी यहां पहुंच रहे है।
अनिल यादव
डीएफओ, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य सवाई माधोपुर

मवेशियों का अकाल के रूप में किसानों के सामने आ रही बाढ़ की विभीषिका

पशुओं को भूखे मरने से बचाने खुद अपना खेत उजाड़ रहे किसान

श्योपुर। संवाददाता

तीन अगस्त को आई बाढ़ की विभीषिका जिलावासी अभी तक झेल रहे हैं। बाढ़ अपने साथ बढ़ी संख्या में मवेशियों का चारा भी बहाकर ले गई। इस कारण इस बार जिले में मवेशियों के लिए चारा का भयंकर संकट आ गया हैं। कई गांवों में तो किसानों ने अपने आजीविका चलाने के लिए जो फसलें बोई थी अब उन फसलों को काटकर किसान उन्हें मवेशियों का चारा बना रहे हैं। खुद अपने हाथों से खड़ी फसलों को काटकर बर्बाद करना कितना मुश्किल काम हैं यह बात सिर्फ वहीं किसान समझ सकता हैं जो इस परिस्थिति से इन दिनों गुजर रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र में किसान बड़ी संख्या में मवेशी भी पालते हैं। फसल के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन कर किसान मवेशियों को अपनी आय का अतिरिक्त साधन बनाते हैं। विगत कुछ सालों में डेयरी फॉर्मिंग के रूप में खेतों पर मवेशियों को पालने का चलन तेजी से बढ़ा हैं। इस धंधे से किसानों की आय कई गुना बढ़ गई, लेकिन अब चारे के संकट ने इस धंधे पर पानी फेरने का काम किया हैं। जिले में बाढ़ की वजह से जो चारा किसानों ने एकत्रित किया था, वह बह गया। अब मवेशियों को खिलाने के लिए चारे का संकट सामने आ गया हैं। ऐसी स्थिति में किसान मवेशियों को बचाने के लिए खुद अपने हाथों से खेतों में खड़ी फसलों की बलि चढ़ा रहे हैं।

जिंदगी तो बचा ली, लेकिन मौत पीछा नहीं छोड़ रही

श्योपुर जिले के 121 गांव 3 अगस्त को आई बाढ़ की चपेट में आकर बर्बाद हुए थे। इन गांवों में हुई बर्बादी के बाद जिंदगी पटरी लौटने तो लगी हैं, लेकिन मौत अभी भी शायद किसानों का पीछा नहीं छोड़ रही। बाढ़ के दौरान लोगों ने अपने पीछे जो सामान सबसे अधिक छोड़ा था वह था मवेशियों का चारा। इन गांवों में चारा पूरी तरह बाढ़ में बहकर या भीगकर नष्ट हो गया। दूसरे गांवों से चारा भी अब मुश्किल मिल रहा हैं। चारा नहीं मिलने से किसानों के मवेशी भूखे मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। मवेशियों को बचाने किसान खुद अपने हाथों से खेतों में बोई गई गेहूं-चना की फसलें काटकर उन्हें मवेशियों का चारा बना रहे हैं।

आसमान पर भूसे का दाम

हमेशा 2 हजार से 3 हजार रूपए में प्रति ट्रॉली (बिट सहित) आसानी से मिल जाने वाला भूसा अब 12 हजार रूपए में भी नहीं मिल रहा हैं। भूसे का संकट इतना अधिक आ गया है कि किसान अपने मवेशियों को बचाने के लिए मुहं मांगे दामों पर भूसा खरीद रहे हैं। हमेशा भूसे के परिवहन पर रोक लगाने वाला प्रशासन इस बार चुप्पी साधे बैठा हैं, क्योंकि किसान इस बार महंगे दाम पर भूसा राजस्थान बेचने नहीं जा रहे बल्कि राजस्थान से महंगे दाम का भूसा खरीदकर ला रहे हैं। श्योपुर में चारे की कमी हो जाने से पड़ोसी राज्य राजस्थान के गांवों में भी किसानों ने चारे के दाम बढ़ा दिए हैं।

बाढ़ से हमारा गांव पूरी तरह डूब गया था। हमसे जो बच सका वह बचा लिया, लेकिन मवेशी का चारा सभी का बह गया। मवेशी भूखे मर रहे हैं, इसलिए मैंने अपने 5 बीघा के खेत में बोई गेहूं की फसल मवेशी के चारे के लिए काटना शुरू कर दी हैं। मेरी तरह ही ओर किसान भी फसलों को पकने से पहले मवेशी का चारा बना रहे हैं।
इशाक खान, किसान, कछार-मेवाड़ा

मैंने विगत वर्ष अपने मवेशियों के लिए दो हजार रूपए बिट में चारा खरीदा था। आज वहीं चारा मुझे 13 हजार रूपए बिट में खरीदना पड़ा हैं। चारे का संकट को हल कराने के लिए शासन-प्रशासन को पहल करने की जरूरत हैं। अगर चारे का स्टॉक जिले को नहीं मिला तो बड़ी संख्या में मवेशी भूख से मर सकत हैं।
रामलखन माहौर,किसान, मठेपुरा

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर कवायद में जुटा पशु पालन विभाग, पशुगणना शुरू

गोरस में बनेगा गिर गाय ब्रीडिंग फार्म एवं रिसर्च सेंटर

भोपाल/श्योपुर। विशेष संवाददाता

आदिवासी विकासखंड कराहल के गोरस क्षेत्र में अब जल्द ही गिर गाय ब्रीडिंग फार्म एवं रिसर्च सेंटर स्थापित होगा। साथ ही यहा चारागाह परियोजना भी विकसित होगी। इसके लिए पशु पालन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। प्रारंभिक चरण में पशुपालन विभाग ने गोरस क्षेत्र में मौजूद गौवंश की गणना कराना शुरू कर दिया है। गणना के बाद प्रस्ताव तैयार कर उसे जिला प्रशासन के माध्यम से स्वीकृति के लिए शासन को भेजने की कार्रवाई की जाएगी। इस सेंटर के गोरस क्षेत्र में बनने के बाद यहां अच्छी नस्ल की गिर गायें तैयार होगी। इससे न सिर्फ श्योपुर जिले को प्रदेश सहित देश में एक नई पहचान मिलेगी, बल्कि इस क्षेत्र के पशुपालकों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी।

यहां बता दें कि गोरस क्षेत्र के गांवों में गिर नस्ल की गायें बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। यहां गिर गाय की जो नस्ल है, वह गुजरात में भी पाई जाती है। गुजरात की गिर नस्ल की गायों को ब्राजील देश द्वारा पाला जाता है। पिछले महीने श्योपुर जिले के दौरे पर आए केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने गोरस में आयोजित पशु पालकों की बैठक में यहां गिर गायों की बहुलता को देखते हुए गोरस को गिर गाय के ऐसे कलस्टर के रूप में विकसित करने के निर्देश अफसरों को दिए कि देश और दुनिया के लोग गिर गाय की अच्छी नस्ल को देखने के लिए गोरस आए। केन्द्रीय मंत्री तोमर के निर्देश के बाद जिले के पशु पालन विभाग ने गोरस क्षेत्र में गिर गाय ब्रीडिंग फार्म एवं रिसर्च सेंटर व चारागाह परियोजना विकसित करने की कवायद शुरू कर दी है।

तैयार होगी अच्छी नस्ल की गिर गाय, बढ़ेगा दुग्ध उत्पादन

पशु पालन विभाग के अफसरों की माने तो गोरस में ब्रीडिंग फार्म और रिसर्च सेंटर खुलने के बाद यहां भोपाल से अच्छी नस्ल के सांड यहां लाए जाएंगे। जिनके जरिए यहां गिर गायों की अच्छी नस्ल तैयार होगी। वर्तमान में यहां गिर गाय दो से चार लीटर तक दूध दे रही है, लेकिन अच्छी नस्ल की गिर गायों की दूध देने की क्षमता बढ़ जाएगी, वे 10 से 12 लीटर तक दूध देने लग जाएगी। जब दूध का उत्पादन बढेगा तो गिर गायों को पालने वाले पशु पालकों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। बता दें कि गिर गाय का दूध बहुत पौष्टिक होता है, इसलिए गिर गाय के दूध की ज्यादा डिमांड रहती है।

तीन सदस्यीय टीम कर रही पशु गणना

गोरस में गिर गाय ब्रीडिंग फार्म एवं रिसर्च सेंटर तथा चारागाह परियोजना स्थापित करने के लिए पशु पालन विभाग ने प्रस्ताव तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। पशु पालन विभाग के अफसरों की माने तो गोरस क्षेत्र में मौजूद पशुओं की गणना के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित कर दी है। यह टीम पशु गणना का काम कंपलीट करने के बाद उसकी रिपोर्ट अफसरों को सौंपेगी। इसके बाद प्रस्ताव तैयार कर उसे जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

मई 2014 में भेजा गया था प्रस्ताव

उल्लेखनीय है कि 15 मई 2013 को ग्वालियर में हुई कृषि उत्पादन आयुक्त की चंबल-ग्वालियर संभागस्तरीय बैठक में यहां गिर ब्रीडिंग सेंटर शुरू करने का प्रस्ताव बनाने के निर्देश श्योपुर के अधिकारियों को दिए गए थे। जिसके बाद मई 2014 में तत्कालीन कलेक्टर जीबी पाटिल द्वारा प्रस्ताव बनाकर पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भोपाल को भेजा गया और पारोंद गांव में 40.675 हेक्टेयर जमीन भी आंवटित की गई। लेकिन तत्समय के अफसरों का तबादला होने के बाद यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। केन्द्रीय मंत्री के निर्देश के बाद इस मामले में फिर से कवायद शुरू हो गई है।

गोरस में गिर गाय ब्रीडिंग फार्म व रिसर्च सेंटर एवं चारागाह परियोजना विकसित की जाएगी, इसके लिए गोरस क्षेत्र में मौजूद पशुओं की गणना की जा रही है। इसके बाद प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसे जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
डॉ एसबी दोहरे,
उपसंचालक, पशु पालन विभाग, श्योपुर

बैठक के बाद कलेक्टर को सौंपा गया व्यापारियों से संबंधित समस्याओं का ज्ञापन

श्योपुर में जड़ी-बूटी आधारित उद्योग स्थापना के लिए करेंगे प्रयास

श्योपुर। संवाददाता

श्योपुर जिला कृषि आधारित जिला है। यहां के वन क्षेत्र में कई तरह की जड़ी-बूटियां भी पाई जाती है। इसलिए श्योपुर जिले में कृषि आधारित उद्योग और जड़ी बूटी आधारित उद्योग स्थापित होने चाहिए। इस दिशा में कन्फरडेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

यह बात श्योपुर में कन्फरडेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की श्योपुर जिला इकाई के द्वारा आयोजित व्यापारी संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कही। व्यापारी संवाद कार्यक्रम में प्रांतीय अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन मुख्य अतिथि और पवन जैन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अतिथियों का कैट की जिला कार्यकारिणी श्योपुर के पदाधिकारियों का स्वागत किया,इसके बाद जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष सूरजमल मंगल ने व्यापारियों की समस्याओं को रखते हुए कहा कि वाणिज्य कर प्रावधान के अंतर्गत जमा 500 व्यापारियों की एफडीआर वाणिज्य कर विभाग में जमा है। 2017 से जीएसटी लग गई है इसके बावजूद भी एफडीआर व्यापारियों को नहीं लौटाई जा रही है। श्योपुर में कृषि व जड़ी बूटी आधारित उद्योगों की जरूरत है। यही नहीं, श्योपुर के व्यापारियों से बिजली बिल मनमाने ढंग से वसूले जा रहे है। इस दौरान प्रांतीय अध्यक्ष ने भरोसा दिया कि श्योपुर में कृषि आधारित और जडी बूटी आधारित उद्योग लगाने के लिए पुरजोर तरीके से प्रयास किए जाएंगे। वहीं बिजली बिलों की समस्या सहित अन्य समस्याओं में सुधार के लिए हर माह श्योपुर में बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के बाद व्यापारियों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौपा गया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री गणेश गर्ग तथा आभार प्रदर्शन उपाध्यक्ष चौथमल सर्राफ ने किया।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)